

# रिफायनरी के कच्चे माल से प्लास्टिक, फार्मा व ऑटोमोबाइल उत्पादों का निर्माण होगा- भजनलाल

## मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एचपीसीएल उद्योग विभाग व उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए

जयपुर, 19 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जॉन में औद्योगिक इकाइयों को डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते (एमओयू) हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 अप्रैल को पंचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन कर देश और प्रदेश को ऐतिहासिक सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से निकलने वाले डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर आधारित सहायक उद्योगों की स्थापना के लिए राजस्थान पेट्रो जॉन (आरपीजेड) विकसित किया गया है। इससे उद्यमी सौधे रिफाइनरी से कच्चा माल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसमें प्लास्टिक, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के उत्पादों का निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिफाइनरी के समीप बोरवासा-कलावा में राजस्थान पेट्रो जॉन (आरपीजेड) 1022 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में लगभग 30 हेक्टेयर भूमि विकसित की जा चुकी है। वहीं,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में रविवार को बालोतरा स्थित राजस्थान पेट्रो जॉन में डाउनस्ट्रीम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एचपीसीएल रिफाइनरी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योगों के बीच 18 त्रिपक्षीय समझौते हुए।

86 औद्योगिक भूखण्डों में से 45 भूखण्डों का आवंटन भी किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान पेट्रो जॉन के द्वितीय चरण में 213 हेक्टेयर में 257 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे, जिनके लिये ए कैटेगरी की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जॉन का तृतीय चरण 780 हेक्टेयर में होगा, जिसमें से 447 हेक्टेयर के लिये कैटेगरी ए की पर्यावरण स्वीकृति लेने हेतु आवेदन किया जा चुका है। इसमें

रामनगर (थोब), सिंधियों की ढाणी, वेदरलाई, बोरवासा विस्तार और खेमाबाबा नगर में लगभग 780 हेक्टेयर भूमि का आवंटन रिको के पक्ष में किया गया है। उल्लेखनीय है कि रिफाइनरी से मुख्य ईंधन के अतिरिक्त, भारी मात्रा में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलेंगे, जो आगामी औद्योगिक इकाइयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल का कार्य करेंगे। पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई), बेंजीन,

टोलुइन और ब्यूटाडाइन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे। इन कच्चे माल के प्रसंस्करण से घरेलू और औद्योगिक उपयोग के विविध उत्पाद, जैसे प्लास्टिक फर्नीचर, कृषि पाइप, पैकेजिंग फिल्म, ऑटोमोबाइल की विशेषताओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। इस अवसर पर एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हैड सीमाता चौधरी सहित, निवेशक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि रिफायनरी से निकलने वाले पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीथीन (एचडीपीई/एलएलडीपीई) बेंजीन, टोलुइन और ब्यूटाडाइन जैसे उप-उत्पादों के आधार पर क्षेत्र में व्यापक सहायक उद्योग स्थापित होंगे।

कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में विकास तेजी से हो रहा है। औद्योगिक इकाइयों के निरंतर विस्तार से रोजगार के अवसरों का व्यापक सृजन हुआ है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग शिखर अग्रवाल ने पंचपदरा रिफाइनरी की विशेषताओं का विस्तृत रूप से उल्लेख किया। इस अवसर पर एचपीसीएल के मार्केटिंग डायरेक्टर अमित गर्ग और पेट्रो केमिकल हैड सीमाता चौधरी सहित, निवेशक एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## एक्सप्रेस वे की दुर्घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। देश में बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक्सप्रेसवे मौत के गलियारों नहीं बने चाहिए और छोटी-छोटी लापरवाहियों को बजह से जान नहीं जानी चाहिए।

मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेके लखवरी और एएस चांदुरकर की बेंच ने बताया कि देश की कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2 प्रतिशत हैं, लेकिन यहां करीब सड़क हादसों में 30 प्रतिशत मौतें होती हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, भारी या कमर्शियल वाहनों को सड़क या किनारे खड़ा करने पर रोक होगी, सिर्फ तब जहां पर ही पार्किंग होगी। हाईवे के किनारे नए ढाबे, दुकान या कोई भी अवैध निर्माण तुरंत रोक दिए जाएंगे। 60 दिनों के अंदर ऐसे सभी

अदालत ने कहा, कुल सड़कों में राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2 प्रतिशत हैं। पर इन पर सड़क दुर्घटनाओं में 30 प्रतिशत मौतें होती हैं।

अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। हर जिले में हाईवे सेपटी टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो सड़क सुरक्षा पर नजर रखेगी। हाईवे पर कैमरे, स्पीड मॉनिटर और इमर्जेंसी सिस्टम (एटीएमएस) लगाए जाएंगे। पुलिस और प्रशासन को नियमित गश्त और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला 2025 में सड़क और तेलिंगाना में हुए बड़े सड़क हादसों के बाद लिया गया, जिनमें कई लोगों की जान चली गई थी।

## मांस, मछली, दवा, अचार नेपाल में लेकर नहीं आ सकते

### नेपाल सरकार ने नये आर्थिक प्रतिबंध लगाए, भारतीय बाज़ार से सौ रूपये अधिक की खरीद पर कस्टम ड्यूटी लगाई

वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण), 19 अप्रैल। नेपाल सरकार के नए आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब भारत-नेपाल सीमा पर साफ दिखने लगा है। वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के 36 नंबर फाटक पर नेपाली प्रशासन की ओर से एक पोस्टर प्रकाश कर कई वस्तुओं को भारत से नेपाल ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल द्वारा लगाए गए इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि डालडा, पेय पदार्थ, मांस, मछली, दवा, अचार, समेत कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भारत से खरीदकर नेपाल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही, सीमा पर तैनात नेपाल पुलिस और आरम्भ पुलिस फोर्स नागरिकों को इस नियम की जानकारी देते हुए सख्ती से पालन करा रही है।

दुकानदारों का कहना है कि नेपाल के लोग रोजमर्रा का सामान खरीदने भारतीय बाजारों में आते थे। नये प्रतिबंधों का असर बाजार की रौनक तथा नेपाल की तराई में रहने वालों के जीवन पर पड़ने वाला है।

नेपाल सरकार के नए फैसले के अनुसार, सीमावर्ती इलाकों के लोग अब भारतीय बाजारों से 100 रुपये से अधिक की खरीदारी बिना शुल्क नहीं कर सकेंगे। तय सीमा से ज्यादा खरीदारी करने पर उन्हें कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इन नए नियमों का असर सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर भी पड़ा है। वाल्मीकिनगर और आसपास के बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है

कि पहले नेपाल के लोग रोजमर्रा के सामान की खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों में आते थे, लेकिन अब सख्ती के कारण उनकी आवाजाही कम हो गई है। इससे बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है और व्यापारियों की आय पर असर पड़ रहा है। नेपाल के इस फैसले का असर केवल भारतीय बाजारों पर, बल्कि नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ने लगा है। जल्द ही सामानों की उपलब्धता और खरीदारी दोनों, प्रभावित हो रहे हैं।

## तृणमूल की रणनीतिकार आई-पैक ने काम बंद किया, कर्मचारियों को 11 मई तक छुट्टी पर भेजा

### शनिवार रात आई-पैक ने कर्मचारियों को ई-मेल भेजकर सूचित किया कि कानूनी अड़चनों के कारण बंगाल में काम फिलहाल रोका गया है

कोलकाता, 19 अप्रैल। बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में उस समय एक चर्चा तेज हो गई, जब तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही चुनावी रणनीतिकार संस्था आई-पैक के कामकाज को अस्थाई रूप से बंद करने की खबरें सामने आईं।

शनिवार देर रात आई-पैक के कर्मचारियों को कथित तौर पर भेजे गए ई-मेल में कानूनी बाध्यात्मों का हवाला देते हुए 20 दिनों की छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इन खबरों को मित्र से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है।

सूत्रों के अनुसार, साल्टलेक स्थित आई-पैक कार्यालय से कर्मचारियों को भेजे गए ई-मेल में कहा गया है कि कुछ कानूनी अड़चनों के कारण बंगाल में कामकाज फिलहाल रोका जा रहा है। कर्मियों को 11 मई तक के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में हाल ही में ईडी द्वारा आई-पैक के

यह माना जा रहा है कि 23 और 29 अप्रैल के मतदान के दौरान आई-पैक की अनुपस्थिति तृणमूल के जमीनी चुनाव प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि तृणमूल ने कहा कि आई-पैक के काम रोकने की खबर निराधार है।

सह-संस्थापक व निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी और संस्था के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद यह कदम उठाया गया है। चर्चा यह भी है कि मतदान की महत्वपूर्ण तारीखों (23 और 29 अप्रैल) के दौरान आई-पैक की अनुपस्थिति तृणमूल के जमीनी चुनावी प्रबंधन को प्रभावित कर सकती है। इन खबरों के मौडिया और उनके बाद तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। पार्टी ने कहा कि आई-पैक द्वारा काम रोकने की खबरें पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं। आई-पैक की बंगाल टीम पूरी तरह सक्रिय है और हमारी चुनावी रणनीति योजनानुसार चल रही है।

आई-पैक और जांच एजेंसियों के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जात हो कि कुछ समय पहले ईडी की छापेमारी के दौरान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई-पैक दफ्तर पहुंची थीं और

### पूर्व केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक अनुभवहीन नेता की नियुक्ति से कूटनीतिक संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है

## ईरान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) यदि ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो उसके पुलों और बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसी बीच ईरान ने नाकबांदी के चलते अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है। टुंग ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पाकिस्तान जाएगा। हालांकि इस बार वार्ता का नेतृत्व कौन करेगा, इसपर संदेह है। जहां, खुद टुंग ने मीडिया से कहा कि इस बार उप राष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षा कारणों से वहां नहीं जाएंगे और पश्चिम एशिया के लिए उनके विशेष दूत स्टीवन विटकोंक वार्ता का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनके दामाद जेड जूसरन टीम में शामिल रहेंगे। वहीं, वाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि वेंस पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी टीम को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।

## अक्षय तृतीया पर गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुले

देहरादून, 19 अप्रैल। उत्तराखंड के चार धामों में शामिल गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट रविवार को अक्षय तृतीया के पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा 2026 का श्रौंगणेश हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम से की। धार्मिक परंपराओं के अनुसार, रविवार को मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची। गंगोत्री धाम में विशेष पूजा-अभिषेक के साथ 12

गंगोत्री धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम से की।

बजकर 15 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गये। इसी तरह मां यमुना की डोली भी शनिदेव महाराज की अर्पणाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि-विधान के साथ 12 बजकर 35 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए।

गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली विशेष पूजा-अर्चना की और देव डोली से आशीर्ष भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। साथ ही, यात्रा मार्गों पर सुचारु यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

## मोदी ने सड़क ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) जनसभा समाप्त करने के बाद वे अपने हेलीकॉप्टर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में सड़क किनारे लगी एक झालमुड़ी की दुकान देखकर उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला रुका, मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। प्रधानमंत्री ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस पल की तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में चार व्यस्त चुनावी रैलियों के बीच झड़झाम में स्वादिष्ट झालमुड़ी का भोजन लिया। चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री का यह अंदाज अब राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी व्यस्तता के बीच प्रधानमंत्री का आम लोगों के बीच पहुंचना उनके लिए सुखद अनुभव रहा।

## तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में आग से 18 मजदूरों की मौत

विरुधुनगर, 19 अप्रैल। तमिलनाडु के जिला विरुधुनगर के कदुनारपट्टी में रविवार दोपहर को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 18 मजदूरों की मौत होने की खबर है, लेकिन प्रशासन ने मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की है। इस हादसे में छह लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने घटना में कई लोगों की मौत पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पुलिस के अनुसार, कदुनारपट्टी में दोपहर में मजदूरों के काम करने के दौरान एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस व

दोपहर में काम के दौरान पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद आग लगी। धमाकों की आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी।

दमककर्मीयों का दल मौके पर पहुंचा और बचाव व राहत कार्य शुरू किया। इस हादसे में वहां काम कर रहे 18 मजदूरों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

## कावेरी नदी में डूबने से 6 लोगों की मौत

मैसूर, 19 अप्रैल। कर्नाटक के मैसूर जिले के केआर नगर क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कावेरी नदी में डूबने से छह लोगों की मौत हो गई। यह घटना अकैश्वर मंदिर के पास स्थित पुराने एडथोरे अकैश्वर स्वामी मंदिर क्षेत्र में हुई। मुख्यमंत्री सिद्धमराया ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।

## प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में भाजपा का प्रचार किया- ममता

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी तंत्र के दुरुपयोग व आचार संहिता के उल्लंघन की चुनाव आयोग को शिकायत करेंगी

कोलकाता, 19 अप्रैल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने उन पर राजनीतिक अभियानों के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के जरिए भाजपा के लिए प्रचार किया है। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी ने कल राजनीतिक अभियानों के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। हम इसकी निंदा करते हैं और चुनाव आयोग से इच्छा की शिकायत करेंगे। टीएमएस प्रमुख ने पीएम पर आदर्श चुनाव आचार

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल किया कि जब महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था तो अभी तक उसे लागू क्यों नहीं किया गया।

संहिता के उल्लंघन का आरोप भी मढ़ा।

गौरतलब है कि शनिवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के बहाने कांग्रेस के साथ-साथ सभी विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की महिलारूप विपक्ष को भ्रूणहत्या के पाप के लिए कड़ी सजा देंगे।

वहीं, अब इसपर पलटवार करते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री को भारत के लोगों

को जवाब देना होगा कि वे अपनी पार्टी के लिए अवैध अभियान क्यों चला रहे हैं? दीदी ने सवाल किया कि जब महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 में ही पास हो गया था, तो इसे अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा-नीत सरकार ने जानबूझकर महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा, भाजपा में इतनी घृष्टता थी कि संख्या बल न होने के बावजूद, वे इसे लोकसभा में लाए। अब भाजपा का पतन शुरू हो गया है।

## उत्साहित ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए एक और नोटिस लाने पर विचार कर रही है। यह कदम उनके पिछले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की ओर से खारिज किए जाने के कुछ ही दिनों बाद उठाया जा रहा है।

सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख पार्टियों इस मामले में चर्चा कर रही है। माना जा रहा कि एक संभावित मसौदा तैयार करने पर काम भी कर रही है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दबाव बनाने की ये विपक्ष की एक कोशिश भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव वाले राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल में एसआईआर, वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े विवाद सामने आए। इससे पहले कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के विवाद सामने आए थे। ऐसे में विपक्ष भी प्रस्ताव लाने का विचार एक राजनीतिक कमेंट का प्रयास भी प्रतीत हो रहा।

## प्रस्तावित परिसीमन का मकसद विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करना है- खड़गे

### कांग्रेस अध्यक्ष ने तमिलनाडु की चुनाव सभाओं में सवाल किया कि भाजपा ने अब तक महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं किया

चेन्नई, 19 अप्रैल। तमिलनाडु चुनाव के बीच महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए पूछा कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने इसे चुनावी मुद्दा बताते हुए कहा कि महिलाओं को अधिकार देने में देरी क्यों हो रही है। कृष्णागिरी और होसुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के बजाय परिसीमन के साथ जोड़कर पेश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा का महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का कदम महिलाओं के लाभ के लिए नहीं, केवल राजनीतिक फायदे के लिए उठाया गया है।

कर रही है। उनका आरोप है कि यह बिल महिलाओं को सशक्त बनाने के बजाय राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लाया गया था। खड़गे ने कहा कि प्रस्तावित परिसीमन का मकसद चुनावी क्षेत्रों को बदलकर विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर करना है। उन्होंने दावा किया कि इसे महिला आरक्षण के नाम पर पेश किया

स्टालिन और राज्य के सांसदों की भी तारीफ की। खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विधानसभा रणनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, महंगाई और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर भी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने नोटबंदी और अन्य फैसलों को भी असफल बताया और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डीएमके, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह एकजुट हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे इस गठबंधन को समर्थन दें। खड़गे ने कहा कि यह लड़ाई लोकतंत्र और समानता की रक्षा के लिए है।